उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास

2178. श्री ईश दत्त यादव: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक विकास के संदर्भ में देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में उद्योगों/कारखानों का प्रतिशत कितना है;

(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों/जिलों की संख्या कितनी है जहां उद्योग नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार उपलब्ध संसाधनों के मद्देनजर उद्योग विहीन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई नीति तैयार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यापक ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) अगस्त, 1991 से मार्च, 1998 तक राज्यवार औद्योगिक निवेश प्रस्तावों की प्रतिशतता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने दिनांक 7 अक्तूबर, 97 की अधिसूचना संख्या का०आ० 714(ई) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर रियायतें प्रदान करने के लिए 53 श्रेणी "क" औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों तथा 70 श्रेणी "ख" औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का अलग-अलग उल्लेख किया है। उत्तर प्रदेश के 35 जिलों को इस सूची में शामिल किया गया है। जिनमें 11 जिले श्रेणी "क" में हैं जिनमें शून्य उद्योग जिले भी शामिल हैं।

(ग) हालांकि नीतियां बनाना तथा राज्यों में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए संसाधनों का आवंटन करने का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, फिर भी केन्द्र सरकार विकास केन्द्र योजना एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना (आई०आई०डी०सी०) तथा परिवहन राजसहायता योजना जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्य के प्रयासों की सहायता करती है।

(घ) विकास केन्द्र योजना।

25 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश में विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले 71 औद्योगिक विकास केन्द्रों की घोषणा की गई है।

एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना (आई०आई०डी०एस)

उक्त योजना के तहत पिछड़े क्षेत्रों में 50 केन्द्रों को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इन केन्द्रों के लिए स्थापना स्थल का चयन राज्य सरकार की सिफारिशों पर किया जाता है।

परिवहन राजसहायता योजना

यह पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिले, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए लागू है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल प्रस्ताव (औ०उ०ज्ञा० †आशय पत्र संख्या)	प्रतिशत
महाराष्ट्र	6210	17.23
गुजरात	5174	14.35
उत्तर प्रदेश	3597	9.98
तमिलनाडु	3580	9.93
आन्ध्र प्रदेश	2491	6.91
हरियाणा	2312	6.41
मध्य प्रदेश	2026	5.62
राजस्थान	1844	5.12
पंजाब	1773	4.92
प० बंगाल	1470	4.08
कर्नाटक	1352	3.75

राज्य / संघ शासित प्रदेश	कुल प्रस्ताव (औ०उ०ज्ञा० आशय पत्र संख्या)	प्रतिशत
दादर और नगर हवेली	1020	2.83
दमन और दीव	484	1.34
दिल्ली	461	1.28
केरल	415	1.15
हिमाचल प्रदेश	364	1.01
पांडिचेरी	347	0.96
बिहार	328	0.91
गोवा	303	0.84
उड़ीसा	260	0.72
असम	84	0.23
जम्मू और कश्मीर	67	0.19
चण्डीगढ़	24	0.07
मेघालय	13	0.04
सिक्किम	10	0.03
अण्डमान और निकोबार	9	0.02
अरूंणाचल प्रदेश	6	0.02
नागालैंड	5	0.01
त्रिपुरा	4	0.01
लक्षद्वीप	1	0.00
मिजोरम	0	0.00
मणिपुर	0	0.00
एक से अधिक राज्य	11	0.03
जोड़	36045	100.00

आई० ई० एम०: लाइसेंसयुक्त क्षेत्र के अधीन मदों हेतु दायर किये गये औद्योगिक उद्यी ज्ञापन आवेदन

एल० ओ० आई०: लाइसेंसयुक्त क्षेत्र के अधीन केन्द्रमदों के संबंध में जारी किये गये आशय-पत्र

Return on Investment in Navaratnas

2179. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the 'Navaratnas' (PSEs) are not having the rate of profit or return as per the prevalent rate of interest on invested capital; and

(b) if so, what are the details there to?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHAT): (a) and (b) No, Sir. The average rate of return in terms of net profit to capital employed in 1996-97 was around 18% which is higher than the prevalent rate of interest on invested capital.

Reaction to Nuclear Testing by India

2180. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that following the testing of nuclear devices by India in May, 1998 some industrialised countries have reacted negatively in the field of economic relations;